Sixteenth Loksabha

span>

Title: Need to provide basic facilities to residents of colonies of South Delhi Parliamentary Constituency affected by Forest Act, 1997.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैडम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में लगभग एक लाख लोग, जो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित हैं और पिछले 50-60 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। उन्होंने लेबर क्लास के रूप में काम करना शुरू किया था। जब उन्होंने वहां पर रहना शुरू किया था, वहां उनके पक्के मकान हैं, सब कुछ है, लेकिन भाटी माइन्स के अंदर एक कॉलोनी है – संजय कॉलोनी, इसी प्रकार से लालकुआं, भीम बस्ती, शम्भू बस्ती और नेब सराय हैं। इन सभी जगहों पर अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रहते हैं और पिछले चार दशकों मे अनुसूचित जाति वर्ग की दुहाई देने वाली और उनकी ठेकेदार बनने वाली सरकारें और मुख्यमंत्री रहे हैं। वहां वर्ष 1998 में एनजीटी आने के बाद, उस लैण्ड को, जहां वे एक लाख अनुसूचित जाति वर्ग के लोग रह रहे हैं, एनजीटी और सरकारों के माध्यम से, तीन बार कांग्रेस की मुख्यमंत्री रहीं, रिज और फॉरेस्ट एरिया में डाल दिया गया। रिज एरिया में डालने की वजह से उनकी बेसिक अमेनिटीज जैसे पानी सप्लाई, सीवर लाइन, सड़क की मरम्मत आदि कोई काम सरकारें रिज एरिया के नाम पर नहीं करती हैं। वहां वे लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। ये सरकारें, जो बार-बार अनुसूचित जाति वर्ग की ठेकेदार बनती थीं, पिछले 50 साल में उनके लिए कुछ नहीं किया। आज भी दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं, वे आरएमबी के चेयरपर्सन हैं।

मैडम, यह एक लाख लोगों का सवाल है, उनको रोज वहां से उठाने की बात होती है और कोई फेसिलिटीज उनको नहीं मिलती हैं। वे बेचारे अपने घर में ईंट नहीं लगा सकते हैं। 50 साल से रह रहे हैं, अगर बेटे की शादी हो गई, अब एक नया कमरा बनाने की सोचें तो वे अपने ही प्रिमाइसेस में उसे नहीं बना सकते हैं। यह मेरा आपसे निवेदन है और यह बात आपके माध्यम से शहरी विकास मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए कि आरएमबी के अंदर जो चेयरमैन हैं, जो राज्य सरकार में इंचार्ज हैं, वे उन घरों का सर्वे कराकर, उनको रिज एरिया से बाहर निकाला जाए और उसके बदले ग्राम सभा की दूसरी जमीन को रिज डिक्लेयर किया जाए। अनुसूचित जाति वर्ग के उन एक लाख लोगों के साथ न्याय किया जाना चाहिए। यह सरकार 'सबका साथ सबका विकास' करने वाली है, यह इनकी तरह तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार नहीं है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष **:**

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

डॉ. कुलमणि सामल और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।